

गोरखपुर क्षेत्रीय बैंक की लाभदायकता का एक संक्षिप्त परीक्षण एवं आय व्यय विश्लेषण : एक सावधिक अध्ययन (1987-1998)

डॉ शिव पूजन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय तिलहर
शाहजहांपुर

शोध सारांश- प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना तथा जनता के हित का ध्यान रखना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक संस्था का यह प्रयत्न होता है कि प्राप्त लाभ की मात्रा न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो, बल्कि सापेक्षिक रूप से भी अधिक हो अर्थात् उस संस्था में प्रयुक्त व अन्य संसाधन की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। लाभदायकता किसी भी व्यावसायिक संस्था के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचकांक होती है, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी। लाभदायकता के अन्तर्गत संस्था में प्रयुक्त संसाधनों की उपार्जन शक्ति का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतया संस्था की लाभदायकता संस्था के वर्तमान अस्तित्व को बनाये रखने में सहायक होती है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश देती है।

प्रस्तुत लेख इसी सन्दर्भ में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कोशों के उपयोग, बैंको को प्राप्त होने वाली आय, ब्याज लाभ एवं उनके व्यय का संज्ञान लेता हुआ बैंक की लाभदायकता का 1987 से 1998 की अवधि के सन्दर्भ में एक संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है और आलोच्य अवधि में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कामकाज को इन मूलभूत संकेतकों के माध्यम से परखने का भी प्रयास करता है

शोध विधि- प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न शाखा प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उनका मन जानने का प्रयास किया गया है, द्वितीयक समक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रमाणित आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते से प्राप्त किया गया है। इसी के साथ ही आर बी आई. द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए निर्देशों तथा उसमें प्रमाणित आँकड़ों का भी उपयोग किया गया है। इस अध्ययन की सीमा का मुख्य आधार आलोच्य अवधि है जिसके आधार पर निष्कर्ष प्रतिपादित किये गए हैं

अध्ययन की उपयोगिता

वर्तमान अध्ययन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नियोजन एवं प्रबन्ध में सहायक होगा। साथ ही वित्तीय प्रबन्धन एवं कुशलता में वृद्धि होगी एवं इसकी कुशलता में वृद्धि से क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त मात्रा में वित्त का प्रवाह होगा तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

भूमिका- 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीकरण का मूल उद्देश्य बैंको को समाजिक आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत करना था, इसलिए लामों को बैंक की प्राथमिकता सूची में गौड़ स्थान दिया गया। यही नहीं यह तर्क भी दिया गया कि सार्वजनिक महत्व की इन सेवाओं में लाभका कोई स्थान नहीं है। किन्तु किसी भी व्यावसायिक क्रिया के लिए लाभ एक अनिवार्य शर्त है और बैंक

इसका अपवाद नहीं हो सकता। सुवृद्ध विकास के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त लाभ अर्जित करना चाहिए जो न केवल उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो बल्कि इतने संचयों का भी सृजन हो सके जिससे वे भविष्य में अधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन की चुनौती स्वीकार कर सकें।

ग्रामीण बैंको की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना एवं उनको बाहर निकालना था क्योंकि राष्ट्रीय बैंकों की पहुँच गाँवों तक नहीं थी अक्टूबर 1975 को जिन 5 बैंको की स्थापना हुई उसमें एक गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है।

तलिका सं० 1

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुल आय एवं कुल व्यय का विवरण

वर्ष	व्याज आय अन्य आय		कुल आय		जमा पर उधार पर परिचालन प्रावधान		कुल लाभ		
	व्याज	अन्य आय	कुल आय	जमा पर व्याज	उधार पर व्याज	परिचालन व्यय एवं संचय	प्रावधान व्यय	कुल लाभ	
1987	861	12	8774	452	1239	193	—	783	91
1988—89	1043	14	1057	556	127	261	—	944	113
1989—90	1784	17	1801	904	210	385	—	1499	302
1990—91	2524	30	2554	1120	251	778	—	2149	405
1991—92	2833	30	2863	1357	271	699	—	2329	534
1992—93	3730	43	3733	1830	274	932	—	3035	738
1993—94	3730	39	4195	2163	303	1278	358	4587	1038
1994—95	4327	342	4669	2163	303	1208	—	3675	995
1995—96	5544	80	5625	2620	331	1278	358	4587	1038
1996—97	6768	58	6826	3445	370	1393	238	5446	1380
1997—98	7469	92	7551	4381	337	1329	53	6100	1451

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से पता लगता है कुल आय व कुल व्यय का अंतर बढ़ने के कारण बैंक लाभ में वृद्धि हो रही है।

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाभों में आलोच्य अवधि में लगभग 15 गुने की वृद्धि हुई है। वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 87 के लाभों में 22 लाख रूपयों की वृद्धि वर्ष 87 की तुलना में 88—89 में 189 लाख रूपयों की वृद्धि हुई। लाखों में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 91—92 की तुलना में 92—93 में 204 लाख रूपये थी। बैंक ने प्रत्येक वर्ष लाभ कमाया है। वर्ष 96—97 में लाभ की राशि 1380 लाख रूपये थी, जो बढ़कर वर्ष 97—98 में 1452 लाख रूपये है इस प्रकार वर्ष 97—98 में गत वर्ष की तुलना में लाखों में 72 लाख रू० की वृद्धि हुई।

लाभानुपात तथा व्यय विश्लेषण

लाभानुपात बैंक की आय धारण क्षमता को अभिव्यक्त करता है अर्थात् लाभानुपात प्रथमतः यह बताता है कि बैंक की आय अर्जन क्षमता कितनी है और दूसरे यह कि जमा व उधार पर, व्याज जनशक्ति व अन्य व्ययों, पर बैंक की नियंत्रण क्षमता कितनी है।

लाभानुपात प्रबंधकीय कार्यक्षमता को लागत नियंत्रण के संदर्भ में स्पष्ट करता है सूत्र रूप में इसे हम प्रकार रख सकते हैं:-

$$\text{लाभानुपात} = \frac{\text{शुद्ध लाभ}}{\text{कुल आय}}$$

(तालिका सं०- 2)

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाभानुपात प्रवृत्ति की विवेचना निम्न तालिका के माध्यम से इस प्रकार है-

(रूपये लाख में)

वर्ष	लाभ (शुद्ध)	कुल आय	लाभानुपात	लाभों की वृद्धि दर प्रतिशत	कुल आय वृद्धि दर प्रतिशत
1986	91	874	0.104	100	100
1987	113	1057	0.107	124	121
1988-89	302	1801	0.167	338	206
1989-90	347	1953	0.177	387	223
1990-91	405	2554	0.158	445	292
1991-92	534	2863	0.186	587	328
1992-93	738	3773	0.195	811	432
1993-94	928	4195	0.221	1019	480
1994-95	995	4669	0.213	1093	537
1995-96	1038	5625	0.184	1141	643
1996-97	1380	6826	0.202	1516	781
1997-98	1452	7551	0.192	1639	864

स्रोत- गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन

उपरोक्त विवरण सं० 2 से स्पष्ट होता है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लाभानुपात सामान्यतया बढ़ता हुआ है। किन्तु कुछ वर्षों में इसमें गिरावट की प्रवृत्ति भी है। वर्ष 1986 में 0.104 था 87 में मामूली वृद्धि के साथ यह 0.107 हो गया। किन्तु अगले वर्ष 88-90 में इसमें लगभग 1 1/2 गुना वृद्धि हुई और यह 0.167 हो गया। 91-92 में इसमें कमी हुई जहां वर्ष 89-90 में यह 0.177 रहा वही घटकर 0.158 रह गया। वर्ष 1993-94 का अनुपात 221 है। किन्तु वर्ष 94-97 में बढ़कर यह 202 हो गया जो वर्ष 93-94 की तुलना में कम ही है। विगत 1 1 वर्षों की अवधि में देखा जाये तो कुल मिलाकर लाभानुपात दो गुना हुआ है। तालिका को देखने से पता चलता है कि **कुल आय में वृद्धि की तुलना में लाभों में तेजी से वृद्धि हुई है**। आलोच्य अवधि में कुल आय में लगभग 9 गुनी वृद्धि हुई है। जबकि लाभों में वृद्धि लगभग 1 5 गुने से भी ज्यादा है। वर्ष 90-91, 94-95 एवं 95-96 में लाभानुपात का गिरना ध्यान देने योग्य है।

ब्याज व्यय विश्लेषण

लाभ तभी अधिक बच पाता है जब व्ययों पर सार्थक एवं सकारात्मक नियंत्रण करें। सामान्यतया बैंक के व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद चुकाये गये ब्याज की होती है। बैंक के लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में जमा, उधार व अन्य पर चुकाया गया ब्याज मद के अन्तर्गत ब्याज की राशि व्यक्त की जाती है लाभ/हानि खाते से यह स्पष्ट नहीं होता कि जमा पर कितना ब्याज है और कितना ब्याज उधार एवं अन्य पर है किन्तु अनुसूची में दिये गये विवरण से स्पष्ट हो जाता है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चुकाया गया ब्याज

तालिका सं० 3.

वर्ष	व्यय किया गया ब्याज	कुल व्यय	रूपये लाख में
			कुल व्यय में ब्याज का प्रतिशत
1986	591	783	75%
1987	682	944	72%
1988-89	1114	1499	74%
1989-90	1147	1607	77%
1990-91	1371	2149	64%
1991-92	1630	2329	70%
1992-93	2104	3035	69%
1993-94	2355	3268	72%
1994-95	2466	3675	67%
1995-96	2951	4587	64%
1996-97	3815	5446	70%
1997-98	4718	6100	77%

स्रोत : गो. क्षेत्र ग्रा. के वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका सं० 3 से ज्ञात होता है कि कुल व्यय में ब्याज की स्थिति में कमी एवं वृद्धि की दशा विद्यमान है प्रारम्भ के तीन वर्षों में इसमें कमी हुई है किन्तु चौथे वर्ष इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 1988-89 के 74 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1989-90 में यह 77 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1990-91 में कम होकर यह 64 प्रतिशत रह गया पुनः बढ़कर 1991-1992 में 70 प्रतिशत हो गया। कमी वृद्धि की मिली हुई स्थिति के साथ यह वर्ष 1996-97 में 70 प्रतिशत है। सर्वाधिक कम हिस्सेदारी वर्ष 1988-89 में 62 प्रतिशत एवं ज्यादा हिस्सेदारी 77 प्रतिशत 1990-91 में रही। पुनः उस स्तर पर यह आलोच्य अवधि में कभी नहीं पहुंच पाया। वर्ष 1997-98 में व्याज व्यय 77 प्रतिशत है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चुकाये गये कुल व्याज में जमा एवं उधार पर व्याज की हिस्सेदारी—
रूपये लाख में

तालिका सं०- 3

वर्ष	कुल ब्याज	जमा पर ब्याज	जमा पर ब्याज %	उधार पर ब्याज%
1986	591	139	76	24
1987	683	127	81	19
1988-89	1114	210	81	19
1989-90	1147	219	80	20
1990-91	1371	251	82	18
1991-92	1630	271	83	17
1992-93	2104	274	87	13
1993-94	2355	279	88	12
1994-95	2455	303	87	13
1995-96	2951	331	89	11
1996-97	3815	370	90	10
1997-98	4718	337	93	7

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो वर्षों को छोड़कर जमा पर ब्याज प्रतिशत प्रत्येक वर्ष बढ़ा है। जमा पर ब्याज की हिस्सेदारी वर्ष 1988-89 में स्थिर रही और वर्ष 1989-90 एवं 1994-95 में इसमें कमी हुई, शेष अन्य वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 87 में हुई जो गत वर्ष के 76 प्रतिशत के स्थान पर 81 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1996-97 में यह हिस्सेदारी 90 प्रतिशत की है। आलोच्य अवधि में यह हिस्सेदारी 76 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच रही। उधार पर ब्याज का प्रतिशत प्रत्येक वर्ष कम होता रहा है। वर्ष 87 एवं 1988-89 में इसमें स्थिरता एवं वर्ष 1991-92 में गत वर्ष की अपेक्षा इसकी हिस्सेदारी में कमी हुई है। शेष वर्षों में अधोगामी प्रवृत्ति ही है। आलोच्य अवधि में उधार पर ब्याज की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच रही है। वर्ष 1996-97 में यह 10 प्रतिशत है। वर्ष 1997-98 में कुल ब्याज में 93 प्रतिशत जमा पर एवं 7 प्रतिशत उधार पर ब्याज है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के व्यय किए गये ब्याज में जमा पर व्याज एवं उधार पर ब्याज में गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन-

तालिका सं०- 5

रूपये लाख में

वर्ष	जमा पर ब्याज	गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	उधार पर ब्याज	गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन%
1986	452	100	139	100
1987	556	123	127	91
1988-89	904	162	210	165
1989-90	928	103	219	104
1990-91	1120	121	251	114
1991-92	1359	121	271	108
1992-93	1830	135	274	101

1993-94	2076	114	279	102
1994-95	2163	104	303	109
1995-96	2620	121	331	109
1996-97	3445	131	337	112
1997-98	4381	127	93	91

तालिका सं०- 5 को देखने से पता चलता है कि मात्रात्मक रूप में जमा पर ब्याज राशि में लगभग 8 गुने की वृद्धि और उधार पर ब्याज की राशि में आलोच्य वर्ष में लगभग 2 1/2 गुना वृद्धि हुई है। किन्तु प्रत्येक वर्ष में परिवर्तन की स्थिति भिन्न है। वर्ष 87 में 86 की तुलना में 6.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु वर्ष 1988-89 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अगले वर्ष 1 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 1990-91 में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु ठीक अगले वर्ष इसमें गिरावट आयी और वढोत्तरी का प्रतिशत 1.22 ही रह गया। वर्ष 1993-94 में गतवर्ष की तुलना में ब्याज व्यय में 4.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके बाद आलोच्य अवधि में यह वृद्धि औसतन 1.5 प्रतिशत की रही। उधार पर ब्याज में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष वार इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। वर्ष 87 में 86 की तुलना में इसमें 21 प्रतिशत कमी हुई सर्वाधिक कमी इन व्ययों में 1992-93 में 23.53 प्रतिशत की थी शेष वर्षों में भी कमी एवं वृद्धि की स्थिति थी। परिवर्तन कभी स्थायी नहीं था।

तालिका 6

जमा पर ब्याज का %	गत वर्ष की तुलना में %परिवर्तन	उधार पर ब्याज %	गत वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
76	—	24	—
	+6.57	19	-21
81	—	19	—
80	-1.00	20	+5.26
82	+2.50	18	-10.00
83	+1.22	17	-5.64
87	+4.82	13	-23.53
88	+1.15	12	-7.70
87	-1.20	13	+8.33
89	+2.29	11	-15.33
90	+1.12	10	-9.10
93	+0.33	7	-30.00

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन

स्थापना व्ययों का विश्लेषण — यह धारणा है कि बैंको में स्थापना व्यय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह धारणा सत्य भी है और असत्य भी। सत्य इसलिए कि यदि केवल आंकड़ों को देखे तो ये व्यय स्पष्टतः बढ़ते ही नहीं अपितु तालिका 5.10 को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल परिचालन व्ययों एवं कुल व्ययों में आलोच्य अवधि में लगभग 7 गुनी वृद्धि हुई है। व्ययों में मात्रात्मक वृद्धि पर लगभग औसत समान

रही है। परिचालन व्यय वर्ष 1986 में कुल व्यय का 23 प्रतिशत था जो 87 में 28 प्रतिशत, 88-89 में 26 प्रतिशत एवं वर्ष 1990-91 में 36 प्रतिशत हो गया आलोच्य अवधि में कभी भी फिर इस प्रतिशत पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद इसकी भागीदारी में कमी हुई जो कम होकर वर्ष 91-92 में 30 प्रतिशत, 92-93 में 31 प्रतिशत, 93-94 में 28 प्रतिशत रह गया किन्तु वर्ष 94-95 में यह 33 प्रतिशत हो गया फिर इसमें कमी हुई और यह वर्ष 96-97 में 27 प्रतिशत एवं वर्ष 97-98 इसका प्रतिशत 28 है।

तालिका सं०- 7

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय और उसमें प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	परिचालन व्यय का प्रतिशत	प्रतिशत परिवर्तन
1986	23	-
1987	28	+12
1988-89	26	-7
1989-90	29	+7
1990-91	36	+24
1991-92	30	-17
1992-93	31	+3
1993-94	28	-10
1994-95	33	+18
1995-96	28	-15
1996-97	27	-4
1997-98	28	+4

उपरोक्त तालिका 7 से स्पष्ट है कि वर्ष 87 में वर्ष 86 की तुलना में परिचालन व्ययों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बाद वर्षवार वृद्धि क्रमशः 7 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 24 प्रतिशत हुई। सर्वाधिक वृद्धि 24 वर्ष 90-91 में रही उसके बाद वर्ष 91-92 में इसमें 17 प्रतिशत कमी हुई पुनः वर्ष 92-93 में इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि पुनः वर्ष 93-94 में 10 प्रतिशत कमी और वर्ष 94-95 में इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बाद के दो वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की कमी और वर्ष 96-97 में 4 प्रतिशत की कमी हुई एवं वर्ष 97-98 में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ब्याज आय विश्लेषण

बैंको की आय का सबसे प्रमुख साधन अग्रिमों एवं विनियोगों पर ब्याज की आय होती है सामान्यतः यह कुल प्राप्तियों का 80 से 90 प्रतिशत होती है तथा इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन लाभदेयता को प्रभावित करता है।

तालिका सं०- 8

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल आय एवं ब्याज

वर्ष	कुल आय	ब्याज आय	ब्याज की कुल पर प्रतिशत	आय एवं परिवर्तन
1986	873	861	98.62	—
1987	1057	1043	98.67	+0.05
1988—89	1801	1784	99.00	+33
1989—90	1953	1932	98.00	-20
1990—91	2554	2524	98.82	+83
1991—92	2863	2833	98.95	+1.3
1992—93	3773	3730	98.86	-.01
1993—94	4195	4156	99.00	+1.14
1994—95	4669	4327	92.67	-6.40
1995—96	5625	5544	92.56	+6.35
1996—97	6826	6768	98.15	+59
1997—98	7551	7459	99.78	-.38

स्रोत : गो0 क्षे0 ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका सं0 8 को देखने से स्पष्ट है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ब्याज आय प्रतिशत कभी भी 98 प्रतिशत से कम नहीं रहा केवल एक वर्ष 94—95 में ब्याज आय का भाग 92.67 प्रतिशत था। वर्ष 1987 में ब्याज आय का प्रतिशत 98.67 प्रतिशत था जो वर्ष 97—98 98.78 प्रतिशत है। वर्ष 94—95 में अन्य आयों में वृद्धि हुई क्योंकि 247.20 लाख रूपये रिजर्व में से खर्चों के लिए लाभ/हानि खाते में डाले गये। तथा अन्य वर्षों की तुलना में कमीशन विनियम दलाली में सर्वाधिक आय 73.91 लाख रूपये हुई। बाद के वर्षों में ब्याज की औसत आय 98 प्रतिशत है। वर्ष 97—98 में ब्याज की आय का भाग 98.78 प्रतिशत है। ब्याज की कुल आय में बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है।

ब्याजेत्तर आय का विश्लेषण—

बैंको को ब्याज के अतिरिक्त मुख्यतः सहायक सेवाओं व अन्य साधनों से आय होती है। यह आय छोटी होने के उपरान्त भी लाभदेयता को प्रभावित करती है। अन्य अन्वयों में कमीशन विनियम एवं दलाली, विनियमों के विक्रय पर लाभ, विनियम व्यवहारों पर लाभ, विनियमों के मूल्यांकन पर लाभ, सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ विविध आय आदि शामिल होती है।

तालिका सं० 9

वर्ष	कुल आय	अन्य आय	अन्य आय का प्रतिशत 1986
1986	873	12	1.37
1987	1057	14	1.32
1988-89	1801	17	1.00
1989-90	1953	21	2.00
1990-91	2554	30	1.18
1991-92	2863	30	1.05
1992-93	3773	43	1.14
1993-94	4195	39	1.00
1994-95	4669	32	7.33
1995-96	5625	80	1.44
1996-97	6826	58	.85
1997-98	7551	92	1..22

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्य आय कुल आय के प्रतिशत के रूप में लगभग स्थिर रही है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लाभदायकता :- गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक वित्तीय संस्था है, जो क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ सामान्य जनता को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर लाभार्जन के लिए प्रयासरत है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना तथा जनता के हित का ध्यान रखना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक संस्था का यह प्रयत्न होता है कि प्राप्त लाभ की मात्रा न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो, बल्कि सापेक्षिक रूप से भी अधिक हो अर्थात् उस संस्था में प्रयुक्त व अन्य संसाधन की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। लाभदायकता किसी भी व्यावसायिक संस्था के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचकांक होती है, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी। लाभदायकता के अन्तर्गत संस्था में प्रयुक्त संसाधनों की उपार्जन शक्ति का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतया संस्था की लाभदायकता संस्था के वर्तमान अस्तित्व को बनाये रखने में सहायक होती है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश देती है।

बैंक के लाभों की सापेक्ष माप लाभदायकता

लाभदायकता आनुपातिक सम्बन्ध अनुपात वित्तीय विवरणों की मदों के बीच सम्बन्ध स्थापना का परिणाम होता है। सामान्यतया लाभदायकता के अध्ययन में निम्न अनुपातों का प्रयोग किया जाता है।

- 1- स्वामित्व कोष पर प्रत्याय
- 2- चुकता पूंजी पर प्रत्याय
- 3- कुल संसाधन पर प्रत्याय

स्वामित्व कोष पर प्रत्याय

यह अनुपात शुद्ध लाभ तथा अंशधारियों के विनियोग स्वामित्व कोष के बीच सम्बन्ध को प्रकट करता है इसकी गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

शुद्ध लाभ कर के बाद

स्वामित्व कोष पर प्रत्याय

स्वामित्व कोष

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्वामित्व कोष में पूंजी एवं संचय शामिल है। यह अनुपात व्यवसाय की कुल लाभ प्रदता अर्थ प्रबन्धन की योग्यता की जांच का एक अच्छा आधार प्रदान करता है। इसकी गणना करना आवश्यक होती है क्योंकि इसी के आधार पर निवेशको के भविष्य का निर्माण होता है। इस अनुपात का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है—

- 1— यह अनुपात अंशधारियों के विनियोग की अर्जन शक्ति निर्धारित करता है विनियोग पर उचित प्रत्याय प्रत्येक संस्था का उद्देश्य होता है।
- 2— संस्था के इस अनुपात की तुलना उसी प्रकार की दूसरी संस्था के अनुपात से करके संस्था में प्राप्त प्रत्याय दर की वाछनीयता निर्धारित की जा सकती है।
- 3— संस्था की भावी अर्जन क्षमता के पूर्वानुमान में यह प्रत्याय दर पर्याप्त सहायक होता है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व कोषो पर प्रत्याय का विवरण

वर्ष	चुकता अंश पूंजी	तालिका 10			(रुपये लाख में) का स्वामित्व कोष पर प्रत्याय%
		संचय	स्वामित्व कोष	शुद्ध लाभ	
	1	2	1+2=3		
1987	25.00	554.26	579.26	113.00	19.50
1988—89	25.00	855.77	880.77	302.00	34.28
1989—90	50.00	1202.56	1252.56	347.00	27.70
1990—91	50.00	1607.95	1667.95	405.00	24.28
1991—92	50.00	2142.38	2192.38	534.00	24.35
1992—93	50.00	2879.96	2929.96	738.00	25.18
1993—94	50.00	3807.54	5857.54	928.00	24.05
1994—95	96.25	4802.45	4898.70	995.00	20.31
1995—96	96.25	5840.00	5936.25	1038.00	17.48
1996—97	100.00	7220.16	7320.16	1380.00	18.85
1997—98	100.00	8671.71	8771.71	1442.00	16.43

स्रोत गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक पतिवेदन।

तालिका स०— 10 से ज्ञात होता है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लाभदायकता,

स्वामित्व कोष के सापेक्ष बढ़के 5 वर्षों के बाद कम हो रही है। वर्ष 1987 में लाभदायकता प्रत्याय 19.50 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 88—89 में 34.28 प्रतिशत हो गया, अगले वर्ष वर्ष 89—90 में यह होकर 27.77 प्रतिशत हो गया। बाद के चार वर्षों में यह प्रत्याय लगभग औसतन 24—25 प्रतिशत के बीच रहा।

वर्ष 95-96 में यह कम होकर 17.48 प्रतिशत हो गया। वर्ष 96-97 में यह प्रत्याय दर 18.85 प्रतिशत थी जो वर्ष 97-98 में 16.43 प्रतिशत है।

3. कुल संसाधन पर प्रत्याय

यह अनुपात संस्था के कुल संसाधन प्रयोग में प्रबन्धकीय कुशलता का माप है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है-

लाभ

कुल संसाधन पर प्रत्याय-100

कुल सांघन

यहां लाभ ब्याज घटाने से पूर्व का होता है।

तालिका सं०- 11

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुल संसाधन पर प्रत्याय का विवरण

वर्ष	कुल संसाधन	लाभ	प्रत्याय
1987	11659	795	6.82
1988-89	16660	1416	8.48
1989-90	21578	1494	6.92
1990-91	26085	1776	6.80
1991-92	28541	2165	7.58
1992-93	32765	2841	8.67
1993-94	38915	3282	8.43
1994-95	45382	3461	7.62
1995-96	54066	3989	7.37
1996-97	62420	5195	8.32
1997-98	75140	6170	8.21

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका सं०- 11 से ज्ञात होता है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुल संसाधन पर प्रत्याय स्थित नहीं है उसमें कमी वृद्धि होती रही है। वर्ष 87 में कुल संसाधन पर प्रत्याय 6.82 प्रतिशत था जो वर्ष 88-89 में बढ़कर 8.48 प्रतिशत हो गया। वर्ष 89-90 में इसमें कमी हुई 6.92 रहा। पुनः 90-91 में और कमी हुई यह 6.80 प्रति रह गया। वर्ष 91-92 में और कमी हुई यह 6.80 प्रतिशत रह गया। वर्ष 91-92 एवं 92-93 में वृद्धि हुई फलस्वरूप 7.58 प्रतिशत एवं 8.67 प्रतिशत था। वर्ष 93-94 में कम होकर पुनः 8.43 प्रतिशत अगले दो वर्ष में और कमी हुई यह भाग 7.62 एवं 7.327 प्रतिशत था वर्ष 96-97 में इसमें वृद्धि हुई यह 8.32 प्रतिशत रहा। वर्ष 97-98 में यह प्रत्याय 8.21 प्रतिशत है।

बैंको को लाभदेयता को प्रभावित करने वाले कारक-

मूलतः वाणिज्यिक उपक्रम होने के कारण बैंक अपनी लाभार्जन क्षमता के प्रति चिन्ता रहित नहीं हो सकते। बैंको की लाभदेयता अनिवार्य है क्योंकि न केवल यही गुण जनता के मन में बैंको के प्रति विश्वास जमा सकता है, अपितु इसके बिना बैंको का कार्य करना भी कठिन हो जायेगा। लाभदेयता में वृद्धि के बिना भी लाभ में वृद्धि हो सकती है लेकिन लाभदेयता में वृद्धि होने के लाभों में अवश्य वृद्धि

होगी, इसलिए समय की आवश्यकता लाभदेयता में वृद्ध करने की है। हाल के वर्षों में बैंको की लाभदेयता गिरने के अनेक तत्व जिम्मेदार रहे हैं। मौद्रिक नीति के अतिरिक्त कई अन्य तत्व बैंको की लाभदायकता को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

1. शाखों का तीव्र बिस्तार

1969 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंको की शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ है। न केवल संख्या की दृष्टि से अपितु कुल बैंक शाखाओं में प्रतिशत की दृष्टि से भी ग्रामीण शाखाओं में भारी प्रगति हुई है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रगति एवं प्रवृत्ति सम्बन्धी रिपोर्ट 1988-89 के अनुसार शारा विस्तार के कारण सुविधा प्राप्त व्यक्तियों की प्रति बैंक संख्या में गिरावट आयी है। जून 69 के अन्त में यह संख्या 65.000 थी जो जनसंख्या तीव्र वृद्धि के बाद भी जून 89 के अन्त में 12000 प्रति बैंक हो गयी है। शाखा विस्तार की प्रगति इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है—

तालिका सं०- 12

	1969					1989				
	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	जोड़	ग्रामीण	अर्द्धशहरी शहरी	शहरी	महानगरीय	जोड़
1 भा० स्टेट बैंक	462	796	163	150	1571	3842	2163	1116	784	7905
2 भा० स्टेट बैंक सह. बैंक	358	375	86	75	894	1404	1171	582	397	5554
3 राष्ट्रकृत बैंक	703	1465	928	1072	4168	12948	5498	4803	4048	27297
योग	1523	2636	1177	1297	6635	18194	8832	6501	5229	38756

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रगति एवं प्रवृत्ति सम्बन्धी रिपोर्ट 88-89 पर आधारित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है। 1969 की तुलना में 1989 में संख्यात्मक दृष्टि से इस प्रकार वृद्धि हुई है—

ग्रामीण शाखाएँ	—	16671	अर्द्धशहरी	—	6196
शहरी शाखाएँ	—	5324	महानगरीय	—	3932

कुल शाखाएँ — 32123

उपरोक्त विवरण के आधार पर देखा जाये तो ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार तेजी से हुआ है। 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंको की लगभग 17 प्रतिशत शाखाएँ थी बढ़कर 1989 में लगभग 48 प्रतिशत हो गयी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 प्रतिशत शाखाओं के स्थान पर 49 प्रतिशत शाखाएँ हो गयी। इस विस्तार के परिणाम स्वरूप अधिक लोगो को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला है। ग्रामीण

शाखाएँ अधिकांश दशाओं में अधिक लाभ नहीं कमा पाती चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का तीव्र विकास होने के कारण हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए उससे बैंकों की कुल लाभदेयता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि नयी हानि उठाने वाली शाखा परिचालन लागत पूरा नहीं कर पाती। विभिन्न शाखाओं का वातावरण, परिचालन के प्रमुख अंगों की सभाव्यता व इनकी कठिनाइयां भिन्न हैं। ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों की शाखाएँ सभावित, कारोबार, जमाराशियों का ढांचा आदि से सम्बन्धित कई दबावों का सामना करती हैं। इसलिए यह घटक ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए कई वर्षों तक लाभ अर्जित करना मुश्किल कर देते हैं।

तालिका सं०- 13

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमाओं का ढांचा

वर्ष	मांग जमा		सावधिक जमा
	चालू खाता	बचत खाता	
1987	5.32	60.62	34.05
1988-89	4.34	58.06	37.60
1989-90	6.39	60.75	32.84
1990-91	7.40	60.32	32.29
1991-92	6.82	57.63	35.77
1992-93	7.42	52.96	39.78
1993-94	3.09	56.40	40.50
1994-95	3.50	57.45	39.04
1995-96	2.63	55.78	41.51
1996-97	2.68	53.19	44.13
1997-98	4.10	52.59	43.31

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि बैंक की चालू और मांग जमाएं कम हुई हैं जबकि सावधिक जमाओं में वृद्धि हुई है।

2. जमाराशियों का ढांचा :-

अधिक ब्याज देने वाली दीर्घ अवधि जमाओं के प्रति जनता की बढ़ती रुचि के परिणाम स्वरूप कुल जमाओं में सावधि जमाओं का हिस्सा है। वास्तव में चालू खातों में जमाराशि का कुल जमाओं में प्रतिशत लगातार कम होता गया है तथा कुल जमाओं में सावधि जमाओं के प्रतिशत में सतत वृद्धि हुई है। जमाराशियों के ढांचे में इस विपरीत परिवर्तन के कारण बैंकों की लाभदेयता पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उनके कोषों की लागत में वृद्धि हो गयी है। दीर्घकालीन जमाओं के प्रति जनता का बढ़ता आकर्षण ऐसी जमाओं पर मिलने वाली उंची ब्याज दर के कारण है।

बचत खातों पर भी ब्याज दर में समय समय पर वृद्धि की गयी है। वर्तमान में बचत खातों पर ब्याज दर 4.0 प्रतिशत जो ग्रामीण बैंकों के लिए 4.5 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दरों में सतत वृद्धि के कारण बैंकों की ब्याज लागत बढ़ी है और इसने लाभदेयता को प्रभावित किया है। तालिका सं०- 5.18 से स्पष्ट है कि बैंक में चालू जमाओं का भाग कम हुआ है, सावधिक जमाओं में वृद्धि हुई, बचत खातों की जमा में भी कमी वृद्धि रही है।

3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋणों का महत्वपूर्ण भाग:-

क्षेत्रीय एवं अन्य वाणिज्यिक बैंकों को उच्च विकास दर तथा न्यायपूर्ण वितरण के श्रेष्ठ निष्पादन के उपकरण के रूपमें पहचाना गया है। गरीबी निवारण व ग्रामीण विकास की रणनीति के कार्यों के लिए संस्थागत साख का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को निश्चित समयावधि में समाज के कमजोर वर्गों को कम ब्याज दर पर साख व अन्य उदार सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य व उप लक्ष्य निर्धारित किये गये है। न केवल इन अग्रिमों से कम ब्याज प्राप्त होता है, अपितु इनकी परिचालन लागत भी उंची होती है। वर्तमान में बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि :-

1. उनकी साख का 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को जाता है।
2. प्रत्यक्ष कृषि ऋण 16 प्रतिशत होना चाहिए।
3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों का 25 प्रतिशत या कुल साख का 10 प्रतिशत समाज के पिछड़े वर्गों को देना चाहिए।
4. गतवर्ष में उनकी कुल जमाओं का 1 प्रतिशत भाग विभेदात्मक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने हेतु उपलब्ध होना चाहिए। इन लक्ष्यों के अतिरिक्त बैंकों को यथासमय घोषित होने वाले गरीबों के उत्थान के कार्यक्रमों के लिए वृद्धिमान ऋण देना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र को बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को किए जाने वाले ऋणों की प्रवृत्ति इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है :-

तालिका 14

सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम का प्रतिशत

	1969	1987	1988	1989
शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों ऋण				
शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम का प्रतिशत	14.6	44.8	45.7	44.6

इस प्रकार बैंक ऋण का एक अच्छा भाग प्राथमिकता क्षेत्र में लगा हुआ है।

तालिका सं०- 15

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

रूपये लाख में

वर्ष	कुल अग्रिम	प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत
1989-90	5524	5171	93.62
1990-91	5950	5503	92.49
1991-92	5736	5277	92.00
1992-93	5832	5362	91.97
1993-94	6614	6299	95.24
1994-95	8528	6764	79.33
1995-96	9710	7293	75.10
1996-97	11361	8651	76.13

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन ।

आलोच्य अवधि में गोरखपुर बैंक के अग्रियों के प्रतिशत के रूप में 1982 के 93.62 प्रतिशत की तुलना में काफी कमी हुई है और यह घटकर 96-97 में 76.13 प्रतिशत हो गया है।

तलिका 15 से स्पष्ट है कि यद्यपि अग्रियों में प्रतिशत के रूप में कुछ कमी आयी है। फिर भी कुल अग्रिम का महत्वपूर्ण भाग प्राथमिकता क्षेत्र में लगा हुआ है। इन ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है। कम ब्याज दर वाले अग्रियों का प्रतिशत अधिक होने के कारण उन अग्रियों का प्रतिशत कम है जिस पर बैंक अधिक ब्याज प्राप्त कर सकता है।

ऋणों की अपर्याप्त व अक्षम वसूली के परिणामस्वरूप कोषों का चक्रीकरण प्रभावित होता है। जिससे लाभों में कमी आती है। यही नहीं वसूली में ढील के कारण अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण दे दे का सामाजिक उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होती।

तलिका सं०- 16

विवरण	जून	मार्च										
वसूली के लिए मांग	90	91	92	93	94	950	95	96	96	97	97	98
	3405	3405	4636	4636	5103	5103	3992	3992	4892	4892	5673	5673
वसूली अतिदेय	1431	1663	1664	2753	1984	2951	2022	2408	2176	2661	2683	3687
	1974	1742	2972	1883	3119	2152	1970	1584	2716	2231	2990	1986
वसूली%	42.	48.	35.9	59.4	38.	57.	50.	60.	44.	54.	47.	65.
	02	83			90	80	66	32	48	39	29	00
अतिदेय%	57.	51.	64.1	40.6	61.	42.	49.	39.	55.	45.	52.	35.
	98	17			10	20	34	68	52	61	71	00

स्रोत : गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन।

बीमार उधोगों की बढ़ती समस्या

बीमार औद्योगिक इकाइयों में ऋण फंस जाने से भी बैंक की लाभदेयता प्रभावित होती है। रूग्णता के अनेक कारण हो सकते हैं। बैंको पर रूग्णता का प्रकोप टल सकता है या कम किया जा सकता है यदि समय पर उधोगों के रूग्णता संकेतक चेतावनी चिन्हों पर बैंक ध्यान दे। ऐसे उधोगों में बैंको का कोष फंस जाने के उसका चक्रीकरण रूक जाता है और लाभदायकता प्रभावित होती है।

कर्जमाफी की घातक प्रवृत्ति

वोटों की घृणित राजनीति के परिणाम स्वरूप चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित हो जाने वाली कर्जमाफी की आत्मघाती घोषणाओं व उनके परिपालन ने सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली की नींव हिला दी है। सदियों से शोषित, साहूकारों की मार सहने वाले छोटे व सीमान्त किसानों के विकास के लिए यदि सरकार कोई राहत या अभिप्रेरण प्रदान करना चाहे तो यह निःसन्देह सुखद है लेकिन इस अभिप्रेरण का स्वरूप यदि लोगों के मन में जायज कर्ज चुकाने के दायित्व का फर्ज मिटा दे तो उससे बुरी प्रवृत्ति दूसरी नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त बैंको में भ्रष्टाचार राजनैतिक दखलंदाजी बढ़ते व्यय प्रदर्शनकारी लागते कठिन प्रतियोगिता नयी योजनाओं आदि से भी बैंको की लाभप्रदता विपरीत रूप में प्रभावित हुई है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की बैंक द्वारा कोशो का समग्र प्रबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है मगर ग्रामीण बैंको की लाभप्रदता प्रभावित हो रही है प्राथमिक क्षेत्रो को आबंटन जमाएं एवं लाभ भी बढे है मगर वसूली कम हो रही है। टाइम डिपाजिट में जनता की रुचि बढी है और बैंक ब्याज के भार को वहन करने में परेशानी का अनुभव कर रहे है।

REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY

1. Rangarajan, C (2000): “Perspectives on Indian Economy – A collection of Essays”, UBS Publishers’ Distributors Ltd. Reddy, Y.V. (2000), Monetary and Financial Sector Reforms in India, A Central Banker’s Perspective, UBS Publishers, New Delhi.
2. Reddy, Y.V. (November 2000): “Fiscal and Monetary Policy Interface: Recent Developments in India”, RBI Bulletin, pp.1257-72.
3. Reddy, Y.V. (2001 b.), “Developments in Monetary Policy and Financial Markets in India”, RBI Bulletin, pp.595-615.
4. Reserve Bank of India (1991) Report of the Committee on the Financial System (Chairman Shri M.Narasimham)
5. Reserve Bank of India, (April 1993) Report of High Level Committee on Balance of Payments, (April 1993) (Chairman Dr.C.Rangarajan).
6. Reserve Bank of India, The Report on Currency and Finance (1998-99, 1999-00 and 2000-01)
7. Reserve Bank of India, Annual Report for the years 1997-2001.
8. Reserve Bank of India (1997) Report of the Committee on Banking Sector Reform (Chairman Shri M.Narasimham)
9. Reserve Bank of India, Annual Statements on Monetary and Credit Policy and Mid-term Reviews of Monetary and Credit Policy for the years 1997-2001.
10. Tarapore S.S. (2000), Issues in Financial Sector Reforms, UBS Publishers.
11. Tarapore, S.S (2002), Twists and Turns in Financial Reforms, UBS Publishers.
12. Address by Dr Y V Reddy, Governor of the Reserve Bank of India, at the Institute of Bankers of Pakistan, Karachi, 18 May 2005.
13. Next Phase of Banking Reforms Underway, By special correspondent. The Hindu. 5 Jun 2005.

14. Banking Reform in India* Abhijit V. Banerjee†, Shawn Cole†, and Esther Duflo, Department of Economics, MIT, June 2004. Article available on Internet.
15. Ayyappan, S., & Sakthivadivel, M. M. (2012). Growth and Trend Analysis of Key Profitability Factors in Indian Scheduled Commercial Banks. *Paripex-Indian Journal of Research*, 1(9).
16. Bapat, D. (2013). Growth, Profitability and Productivity in Public Sector Banks: An Assessment of Their Interrelationship. *The IUP Journal of Bank Management*, XII(3), 49–57.
17. Chaudhary, K., & Sharma, M. (2011). Performance of Indian Public Sector and Private Sector Banks: A Comparative Study. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 2(3), 249–256.
18. Chand, R and S K Srivastava (2014): “Changes in the rural labour market and their Implication for Agriculture,” *Economic & Political Weekly*, Vol 49, No 10, pp 47-54.
19. Chand, R., R Saxena and S Rana (2015): “Estimates and Analysis of Farm Income in India, 1983-84 to 2011-12,” *Economic & Political Weekly*, Vol 50, No 22, pp 139-145.